दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, सोमवार 10 मई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 219

महत्वपूर्ण एवं खास

केन्द्र ने राज्यों को अब तक कोविड वैक्सीन की 17 करोड़ 56 लाख से अधिक डोज निःशुल्क उपलब्ध कराईं

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग के साथ सरकार के सर्वांगीण दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार के साथ, टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण की उदार और त्वरित रणनीति एक मई से लागू की गयी है। 28 अप्रैल से नये पात्र जनसंख्या समूहों के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। संभावित लाभार्थी सीधा कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 17.56करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक प्रदान की हैं। इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 16,83,78,796 खुराक हैं। अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोविड टीके की 72 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं। नकारात्मक संतुलन वाले राज्य टीके की आपूर्ति से ज्यादा उपभोग (अपव्यय सहित)दर्शा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए गए टीके को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 46 लाख से अधिक खुराक दी जाएंगी।

दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह बढ़ी, मेट्रो का संचालन भी बंद

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एक हफ्ते के लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा अभी ढिलाई देने का समय नहीं आया है. सीएम ने कहा की इस बार लॉकडाउन और सख्त होगा. कल सुबह से दिल्ली मेट्रो भी बंद रहेगी. यानी अब दिल्ली में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. केजरीवाल ने कहा कि व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं और अलग-अलग वर्ग के लोगों से बात हुई है और सब का यह मानना है कि कोरोना के मामले कम तो हुए हैं लेकिन अभी सख्ती की जरूरत हैं.

यूपी में कोरोना हुआ खतरनाक, 17 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

लखनऊ (आरएनएस)। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने कर्फ्यू की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। आज के जारी आदेश के अनुसार अब 17 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। इससे पहले आंशिक तौर पर लगाए कर्फ्यू की अवधि सोमवार सुबह समाप्त हो रही थी, लेकिन नए आदेश के बाद अब यह पाबंदियां 17 मई तक जारी रहेंगी। फिलहाल यह व्यवस्था इसी हफ्ते के लिए की गई है। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते की स्थिति देखते हुए क्या फैसला होता है। सरकार ने कर्फ्यू की अवधि बस बढ़ाई है, पहले के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है। बाजार बंद रहेंगे और शहरों में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगी हुई है। हालांकि, औद्योगिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वैश्विक राहत सामग्री का आवंटन और आपूर्ति प्रभावी ढंग हो

» केंद्र सरकार ने किया सुनिश्चित

नईदिल्ली (आरएनएस)। विश्व समुदाय कोविड महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के मामलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की चुनौतियों से निपटने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करते हुए लगातार मदद कर रहा है। केंद्र सरकार निरंतर यह सुनिश्चित करती रही है कि, इस संकटपूर्ण समय के दौरान उसके राहत कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वैश्विक सहायता व राहत सामग्री का आवंटन और आपूर्ति प्रभावी ढंग से तथा तत्काल किया जाए।

अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6,608 ऑक्सीजन कनसेनट्रेटर, 3,856 ऑक्सीजन सिलेंडर, 14 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 4,330 वेंटीलेटर / बाई पीएपी / सी पीएपी और 3 लाख से ज्यादा रेमेडिसविर शीशियों को अब तक वितरित किया जा चुका है।

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आगे बढ़ रहा है और देश में अब तक कोविड वैक्सीन के 16.94 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक कुल टीकाकरण की 66.78 प्रतिशत खुराक दस राज्यों के लोगों को दी गई हैं। 18-44 वर्ष आयु वर्ग के 2,94,912 लाभार्थियों ने आज कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाया और पिछले 24 घंटों के दौरान 30 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 17,84,869 टीके लगाए गए। नीचे दी गई तालिका में अब तक 18-44 वर्ष की आयु के लिए दी गई वैक्सीन की संख्या दर्शाई गई है। पिछले 24 घंटों में 20 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। टीकाकरण अभियान के 113वें दिन 20,23,532 टीके लगाए गए। टीकाकरण के 16,722 सत्रों में 8,37,695 पात्र लाभार्थियों को पहलीखुराक और 11,85,837 लाभार्थियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। भारत में आज तक 1,83,17,404 कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 82.15 प्रतिशतहै। पिछले 24 घंटों में 3,86,444 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में 10 राज्यों का योगदान 75.75 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,03,738 नए रोगी सामने आये हैं। पिछले 24 घंटों मेंदस राज्यों का नये मामलों में 71.75 प्रतिशतयोगदान रहा है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 56,578 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कर्नाटक से 47,563 और केरल में 41,971 नए मरीज सामने आए। देश भर में अब तक कुल 30.22 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की गई है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी दर 21.64 प्रतिशतहै, जैसे कि नीचे दिए गए ग्राफ दर्शाया गया है। भारत में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 37,36,648 तक पहुंच गई है। यह देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 16.76 प्रतिशतहिस्सा है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों में 13,202 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत के कुल सक्रिय मामलों में 13 राज्यों का 82.94 प्रतिशतहिस्सा है। देश में कोविड से मृत्यु दर कम हो रही है और वर्तमान में यह 1.09 प्रतिशतहै।

पिछले 24 घंटों में 4092 कोविड मरीजों की मौत हुई है। अब हो रही मौतों में 74.93 प्रतिशतरोगी दस राज्यों से हैं। महाराष्ट्र में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 864 है। वहीं कर्नाटक में इसबीमारीसे482 लोगों की मृत्यु हुई है। 20 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति मिलियन जनसंख्या पर होने वाली मौतों की संख्या राष्ट्रीय औसत (176) से कम है। 16 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति मिलियन जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु राष्ट्रीय औसत से अधिक है। चार राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से किसी भी रोगी की मौत की सूचना नहीं है। ये दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और लक्षद्वीप हैं।

केंद्र ने कोविड के चलते 25 राज्यों में पंचायतों को दिया 8923.8 करोड़ का अनुदान अग्रिम रूप से जारी किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की। ये अनुदान पंचायती राज संस्थानों की सभी तीन श्रेणियों-गांव, प्रखंड और जिला के लिए हैं। शनिवार को जारी राशि वर्ष 2021-22 के लिए ' मुक्त अनुदान' की पहली किस्त है। इसका उपयोग आरएलबी द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम संबंधी तथा राहत उपायों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, यह इस महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों के संसाधनों को बढ़ाएगा। जारी अनुदान की राज्य वार राशि संलग्न है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति तथा पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्धता शामिल है। लेकिन व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए, मुक्त अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के लिए इस शर्त को छोड़ दिया गया है।

इरेडा और एनएचपीसी ने तीन सौ से अधिक कर्मचारियों का टीकाकरण किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) और एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से अपने समूह के 18 से 44 साल की आयुवर्ग के कर्मचारियों के लिये 7 और 8 मई को इरेडा के नई दिल्ली स्थित मुख्य व्यवसायिक कार्यालय में एक दो दिवसीय कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया।

यह माननीय राज्य मंत्री आर के सिंह विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक किया गया। संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सभी पात्र कर्मचारियों को शीघ्रता से प्रतिरक्षित करने के उद्देश्य और उसे पूरा करने के लिये इरेडा, एनएचपीसी, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, एमएचए, पीएफसी, आरईसी, बीएचईएल, बीबीएमबी, एमएमटीसी, नीपको, पीटीसी, एनएसपीसीएल और सीईए के कुल 317 कर्मचारियों को शिविर में टीका लगाया गया। टीकाकरण शिविर में सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। इस अवसर पर प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा ने रेखांकित किया कि यह सुरक्षा और विश्वास को सुनिश्चित करने का प्रयास है जिससे स्वस्थ कार्यबल को तैयार किया जा सके। यह सामान्य जीवन की तरफ लौटने में मदद करेगा, जिससे अर्थव्यस्था तेजी से स्वस्थ होगी। दास ने एनएचपीसी और अपोलो अस्पताल को सहयोग और समर्थन के लिये धन्यवाद दिया। इरेडा ने कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर को रोकने के लिये कई कदम उठायें हैं। इसने एक अनुकरणीय 'कोविड केयर रिस्पॉन्स टीम' का गठन किया गया, जो जून 2020 से लगातार कोविड-19 संक्रमित कर्मचारियों और उनके परिवार वालों की देखभाल कर रही है। टीम ने अब तक 77 कर्मचारियों, कर्मचारियों के परिवार के 27 सदस्यों एवं 17 अन्य को समय-समय पर परामर्श देकर, और सभी जरूरी सहायता जैसे खाने और दवाओं की नियमित आपूर्ति करना, अस्पताल में भर्ती कराना, प्लाज्मा डोनेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि के जरिये मदद की है।

सेना चिकित्सा कोर और शॉर्ट सर्विस कमीशन के पूर्व चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के आदेश जारी

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व आर्मी मेडिकल कोर (एएमसी)/शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज महानिदेशालय (डीजी एएफएमएस) को आदेश जारी किया है। टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत, 2017 और 2021 के बीच रिटायर हुए 400 पूर्व एएमसी/एसएससी चिकित्सा अधिकारियों को अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भर्ती किए जाने की उम्मीद है।

8 मई के आदेश में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के समय प्रदान वेतन से मूल पेंशन में कटौती करके एक निश्चित मासिक एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी,

साथ ही जहां भी विशेषज्ञ वेतन ज़रूरी होगा वह दिया जाएगा। यह राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी और किसी अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। भर्ती किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारियों को नागरिक मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट होना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा कोविड-19 की स्थिति से उबरने के लिए नागरिक प्रशासन की सहायता हेतु अतिरिक्त जनशक्ति जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एएफएमएस ने पहले ही विभिन्न अस्पतालों में स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट एवं सहयोगी स्टाफ समेत अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती कर दी है, जबकि एएफएमएस के शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड डॉक्टरों को दिनांक 31 दिसंबर, 2021 तक सेवा विस्तार दिया गया है जिससे 238 और डॉक्टरों ने संख्या बढ़ी है। हाल ही में एएफएमएस से सेवानिवृत्त चिकित्सा पेशेवरों को भी स्वास्थ्य पेशेवरों के कार्य बल को और मजबूत करने के लिए फिर से तैनात किया गया है।

इसके अलावा देश के सभी नागरिकों को ई-संजीवनी ओपीडी पर ऑनलाइन निःशुल्क परामर्श देने के लिए पूर्व रक्षा चिकित्सकों को मैदान में उतारा गया है।इस सेवा का लाभ वेबसाइट पर लिया जा सकता है। 51 उच्च दबाव वाले पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लीनिकों में तीन महीने के लिए नाइट ड्यूटी के लिए अतिरिक्त संविदा कर्मचारियों को भी अस्थायी रूप से काम पर रखा गया है ताकि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

रेल विभाग ने विभिन्न राज्यों को 4,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रेल वर्तमान समय में मौजूद चुनौतियों का सामना करते हुए और नए उपायों की तलाश के साथ देश के विभिन्न राज्यों की मांग पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान को निरंतर जारी रख लोगों को राहत पहुंचा रही है।

रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 268 टैंकरों में लगभग 4200 मीट्रिक टन चिकित्सा उपयोग हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 68 ऑक्सीजन एक्सप्रेस की यात्रा पूरी हो चुकी है। भारतीय रेल, राज्यों की मांग पर यथासंभव मात्रा और कम से कम समय में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर लगातार काम कर रही है। भारतीय रेल द्वारा शुरू किए ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभियान के अंतर्गत अब तक महाराष्ट्र को 293 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 1230 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 271 मीट्रिक टन, हरियाणा को 555 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन, राजस्थान को 40 मीट्रिक टन और दिल्ली को 1679 मीट्रिक टन ऑक्सीज़न की आपूर्ति की गई। अब रेलवे ने और अधिक शहरों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी है और इस क्रम में आज कानपुर में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एलएमओ की ढुलाई करने वाले टैंकरों और कन्टेनरों का आवागमन टोल-फ्री

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों को उपयोगकर्ता शुल्क में छूट प्रदान की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के कारण पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की अभूतपूर्व मांग है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले कंटेनरों को दो महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक एंबुलेंस जैसी अन्य आपातकालीन वाहनों की तरह ही माना जाएगा।

हालांकि टोल प्लाजा पर फास्टैग

लागू होने के बाद प्रतीक्षा समय लगभग शून्य हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहले से ही ऐसे वाहनों को चिकित्सा ऑक्सीजन का त्वरित और निर्बाध परिवहन करने के लिए निर्बाध मार्ग प्रदान किया जा रहा है। एनएचएआई द्वारा अपने सभी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को यह भी निर्देश जारी किया गया है कि वे महामारी से लड़ने के लिए सरकारी और निजी प्रयासों की सहायता करें जिससे उन्हें सक्रिय रूप से सहायता प्राप्त हो सके।

कोविड-19 के प्रकोप के कारण पूरे देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मांग उत्पन्न हो गई है। वर्तमान समय में चल रहे इस संकट के समय में, कोविड-19 से गंभीर रूप से प्रभावित रोगियों की जान बचाने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति बहुत ही आवश्यक है। टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान में छूट देने से राष्ट्रीय राजमार्गों पर मेडिकल ऑक्सीजन का आवागमन तीव्र गति से सुनिश्चित हो सकेगा।

हिमंत बिस्व सरमा होंगे असम के नए सीएम, सर्बानंद सोनोवाल ने सौंपा इस्तीफा

गुवाहाटी (आरएनएस)। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस (एनईडीए) के संयोजक हिमंत बिस्व सरमा रविवार को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता निर्वाचित हुए और उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार बनाने के लिए जल्द ही आमंत्रित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने रविवार को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा और भाजपा के प्रदेश पार्टी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और हाफलांग से नव निर्वाचित विधायक नंदिता गार्लोसा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। चूंकि और किसी के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा गया तो ''सरमा को भाजपा विधायक

दल का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया है।'' वहीं, असम के अगले सीएम पद के चेहरे को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

तोमर ने कहा कि भाजपा, असम गण परिषद (एजीपी) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ जल्द ही बैठक करेगी। एजीपी विधायक दल ने भी रविवार को बैठक की। पार्टी ने घोषणा की कि वह भाजपा विधायक दल द्वारा निर्वाचित नेता का समर्थन करेगी। इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा दे दिया। परंपरा के अनुसार राज्यपाल ने अगली सरकार के गठन तक सोनोवाल से पद पर बने रहने को कहा।

गौरतलब है कि असम के नए मुख्यमंत्री को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच, राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सोनोवाल और हिमंत बिस्व सरमा ने पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में शनिवार को मुलाकात की थी। भाजपा ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा में 60 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद से नौ और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने छह सीटें जीतीं।